

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 296/2022

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह,
2. गोविन्द सिंह पुत्र रिछपाल सिंह,
जाति राजपूत, निवासी गुढागौडजी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

—आवेदक

बनाम

1. श्रवण सिंह पुत्र रिसाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुढागौडजी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।
2. रमाकान्त पुत्र सांवरमल, जाति महाजन, निवासी गुढागौडजी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।
3. किशनलाल पुत्र अशोक कुमार, जाति महाजन, निवासी गुढागौडजी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं राज0 हाल जयपुर राज0।
4. श्री रामसिंह राजावत वर्तमान एस0डी0एम0, उदयपुरवाटी।

— अनावेदकगण

— — —
प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण


उपस्थित:-

1. श्रीमती मीना कुमारी, अभिभाषक- आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अरविन्द सैनी, अभिभाषक- अनावेदक सं0 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- अनावेदक सं0 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

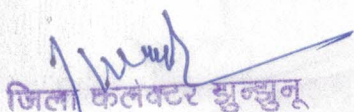
दिनांक 14.11.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 जा0फौ0 वास्ते ट्रांसफर करवाने मु0न0 03/2015 उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह पार्टी नं0 1 आगामी तारीख पेशी 09.09.2022 एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी निम्नानुसार श्रीमान् की सेवामे पेश है ग्राम टोडी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 711, 722 मे विवादित दुकान मय छज्जा स्थित है जिस पर कदीम से निगरानीकार का कब्जा रहा है और जिसमे कपडे विक्रय करने की दुकानदारी निगरानीकार करते आये है। अप्रार्थीगण श्रवण सिंह वगैरह ने एक फर्जी लिखावट लिखकर रमाकान्त व किशनलाल द्वारा निगरानीकार की दुकान को क्य करना बताकर अपनी होना बताया है लेकिन क्योंकि अप्रार्थीगण का ना तो कब्जा था ना ही कोई हक व अधिकार था इसलिए वह प्रार्थीगण के शोरूम पर ताकत के बल पर कब्जा करने मे सफल नही रहा तो उसके पुलिस थाना गुढागौडजी से मिलकर और राजनैतिक दबाव बनाकर अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 परिवार नं0 1 एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी के यहां दिनांक 09.08.2015 को पेश करवा दिया जिस पर एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी ने निम्न कार्यवाही उक्त इस्तगासे मे की:- “आज यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी पुलिस थाना गुढागौडजी ने इस आशय का पेश किया है कि ग्राम टोडी मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 711 व 722 मे एक दुकान एक छज्जा के कब्जे एवं स्वामित्व को लेकर पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 के मध्य मे विवाद है।”


लक्ष्मण सिंह कुडी

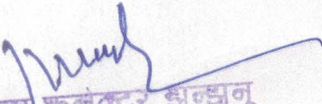
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में थानाधिकारी गुढागौडजी का उक्त विवाद संबंधी न तो शपथ पत्र है ना ही ऐसा कोई सबूत पेश किया है जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम टोडी के भूमि खसरा नम्बर 711 व 722 में बनी दुकान एवं छज्जा को राजहक में कुर्की की कार्यवाही की जा सके। अतः प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर पार्टी नं० 1 व पार्टी नं० 2 को नोटिस जारी हो पत्रावली वास्ते जबाब पार्टी नं० 1 व पार्टी नं० 2 दिनांक 31.08.2015 को पेश हो।" इसी दौरान गैरनिगरानीकार श्रवण सिंह ने जिला जज झुंझुनू के यहां श्रवण सिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरह रेगुलर दावा कब्जा प्राप्त करने का कर दिया जिसका मु०न० 5/15 है जो ट्रांसफर होकर ए०डी०जे० नं० 1 के यहां दर्ज हुआ जिसके मु०न० 47/15 है और वाद दिनांक 04.07.2019 को खारीज हो गया जिसमें गैरनिगरानीकार श्रवण सिंह का ना तो कभी कब्जे में होना माना और ना ही उसे कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी माना और श्रवण सिंह का नियमित सूट खारीज कर दिया। प्रार्थीगण ने दिनांक 19.07.2019 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 1 के निर्णय व डिक्री सहित एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें एस०डी०ओ० उदयपुरवाटी से निवेदन किया गया कि अब उक्त अन्तर्गत धारा 145 जा०फौ० की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है इसलिए अन्तर्गत धारा 145 जा०फौ० की कार्यवाही ड्रेप की जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है और बोगस परिवाद बिना आधार के पेडिंग कर रखा है जिससे प्रार्थीगण के समय व धन की बर्बादी हो रही है और अनावश्यक कार्यवाही चल रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण मु०न० 3/2015 सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह अ०धारा 145 की कार्यवाही को अन्य एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर की जावे जिससे वह माकूल आदेश पारित कर सके। जब सिविल कार्यवाही श्रवण सिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरह मु०न० 5/2015 (47/15) रेगुलर सूट था जिसमें श्रवण का ना तो कभी कब्जा माना और ना ही श्रवण सिंह को कब्जा लेने का अधिकारी माना, जब गुण-अवगुण पर सिविल न्यायालय ने जब निर्णय कर दिया तक 145 जा०फौ० की कार्यवाही चालू रखना किसी भी रूप में न्यायसंगत व उचित नहीं है। एस०डी०एम० उदयपुरवाटी, उदयपुरवाटी के विधायक व राज्यमंत्री के दबाव में है इस कारण 8 साल बाद में एस०एच०ओ० से मौके की रिपोर्ट मंगाकर प्रार्थीगण की दुकान को नाजायज रूप से कुर्क करना चाहता है जबकि इस संबंध में सिविल न्यायालय का फैसला आ चुका है। दिनांक 26.08.2022 को एस०डी०एम० उदयपुरवाटी के न्यायालय ने एलानियां रीडर को कहा कि एस०एच०ओ० गुढा की रिपोर्ट तुरन्त मंगवाओं। मैं इस दुकान को तुरन्त कुर्क करूंगा। प्रार्थीगण भी वहीं खड़े थे। एस०डी०एम० उदयपुरवाटी को कहा कि हमारा ए०डी०जे० साहब के यहां फैसला हो चुका है, हम जीते हुए हैं, हमारी दुकान कैसे कुर्क कर सकते हो तो एस०डी०एम० साहब ने कहा कि मेरे को नौकरी करनी है। मैं तो कुर्क करूंगा आपको जो कार्यवाही करनी हो वो करों। इस प्रकार प्रार्थीगण को एस०डी०एम० उदयपुरवाटी के यहां न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय हुआ है, ऐसा भी महसूस होना चाहिए। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त मुकदमा किसी अन्य एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर किया जावे जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके। एस०डी०एम० उदयपुरवाटी श्रीमान्जी का अधीनस्थ न्यायालय है जिस पर सुपरविजन के अधिकार श्रीमान्जी को हैं और एक एस०डी०एम० के यहां से दूसरे एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर करने के अधिकार भी श्रीमान् जी को हैं इसलिए प्रार्थी को मुकदमा दूसरे एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर किया जावे जिसके लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि न्यायालय एस०डी०एम० उदयपुरवाटी के यहां विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह पार्टी नं० 1 मु०न० 3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा०फौ० को अन्य दूसरे एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर किया जावे जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर एस०डी०एम० उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। एस०डी०एम० उदयपुरवाटी ने पत्रांक 975 दिनांक 29.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि बिन्दू सं० 1 में अंकित तथ्य मनगढनत एवं निराधार है। थानाधिकारी गुढागौडजी से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी०आर०पी०सी० बाबत दोनो पक्षों में दुकान के कब्जे को लेकर विवाद होने के कारण प्राप्त होने पर दर्ज


जिला कलेक्टर झुंझुनू

रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण पार्टी नं० 1 व 2 को जबाब/साक्ष्य हेतु नोटिस जारी किये गये। दुकान के कब्जे के स्वामित्व को लेकर दोनो पक्षों में जो विवाद है उसका गुणावगुण के आधार पर निर्धारण के लिए पार्टी नं० 1 व पार्टी नं० 2 की विधिवत् सुनवाई की जा रही है। यदि प्रार्थी उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर कराना चाहता तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई ऐतराज/आपत्ति नहीं है। बिन्दू सं० 2 में अंकित तथ्य निराधार एवं बेबुनियाद है। प्रस्तुत प्रकरण काफी पुराना है जो दिनांक 04.08.2015 का दर्ज है जिसमें विधिवत् सुनवाई जी जा रही है। बिन्दू सं० 3 में अंकित तथ्य प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू सं० 4 कानूनी है। इस न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह पार्टी नं० 1 मु०न० 3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा०फौ० में नियमानुसार विधिवत् सुनवाई की जा रही है। श्रीमान् द्वारा उक्त प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई ऐतराज/आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि गैरनिगरानीकार श्रवण सिंह ने जिला जज झुंझुनू के यहां श्रवण सिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरह रेगुलर दावा कब्जा प्राप्त करने का कर दिया जिसका मु०न० 5/15 है जो ट्रांसफर होकर ए०डी०जे० नं० 1 के यहां दर्ज हुआ जिसके मु०न० 47/15 है और वाद दिनांक 04.07.2019 को खारीज हो गया जिसमें गैरनिगरानीकार श्रवण सिंह का ना तो कभी कब्जे में होना माना और ना ही उसे कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी माना और श्रवण सिंह का नियमित सूट खारीज कर दिया। प्रार्थीगण ने दिनांक 19.07.2019 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 1 के निर्णय व डिक्री सहित एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें एस०डी०ओ० उदयपुरवाटी से निवेदन किया गया कि अब उक्त अन्तर्गत धारा 145 जा०फौ० की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है इसलिए अन्तर्गत धारा 145 जा०फौ० की कार्यवाही ड्रेप की जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है और बोगस परिवाद बिना आधार के पेडिंग कर रखा है जिससे प्रार्थीगण के समय व धन की बर्बादी हो रही है और अनावश्यक कार्यवाही चल रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण मु०न० 3/2015 सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह अ०धारा 145 की कार्यवाही को अन्य एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर की जावे जिससे वह माकूल आदेश पारित कर सके। जब सिविल कार्यवाही श्रवण सिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरह मु०न० 5/2015 (47/15) रेगुलर सूट था जिसमें श्रवण का ना तो कभी कब्जा माना और ना ही श्रवण सिंह को कब्जा लेने का अधिकारी माना, जब गुण-अवगुण पर सिविल न्यायालय ने जब निर्णय कर दिया तक 145 जा०फौ० की कार्यवाही चालू रखना किसी भी रूप में न्यायसंगत व उचित नहीं है। एस०डी०एम० उदयपुरवाटी, उदयपुरवाटी के विधायक व राज्यमंत्री के दबाव में है इस कारण 8 साल बाद में एस०एच०ओ० से मौके की रिपोर्ट मंगाकर प्रार्थीगण की दुकान को नाजायज रूप से कुर्क करना चाहता है जबकि इस संबंध में सिविल न्यायालय का फैसला आ चुका है। दिनांक 26.08.2022 को एस०डी०एम० उदयपुरवाटी के न्यायालय ने एलानियां रीडर को कहा कि एस०एच०ओ० गुढा की रिपोर्ट तुरन्त मंगवाओं। मैं इस दुकान को तुरन्त कुर्क करूंगा। प्रार्थीगण भी वहीं खड़े थे। एस०डी०एम० उदयपुरवाटी को कहा कि हमारा ए०डी०जे० साहब के यहां फैसला हो चुका है, हम जीते हुए हैं, हमारी दुकान कैसे कुर्क कर सकते हो तो एस०डी०एम० साहब ने कहा कि मेरे को नौकरी करनी है। मैं तो कुर्क करूंगा आपको जो कार्यवाही करनी हो वो करें। इस प्रकार प्रार्थीगण को एस०डी०एम० उदयपुरवाटी के यहां न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय हुआ है, ऐसा भी महसूस होना चाहिए। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त मुकदमा किसी अन्य एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर किया जावे जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके। एस०डी०एम० उदयपुरवाटी श्रीमान्जी का अधीनस्थ न्यायालय है जिस पर सुपरविजन के अधिकार श्रीमान्जी को है और एक एस०डी०एम० के यहां से दूसरे एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर करने के अधिकार भी श्रीमान् जी को है इसलिए प्रार्थी को मुकदमा दूसरे एस०डी०एम० के यहां ट्रांसफर किया जावे जिसके लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवामें पेश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय एस०डी०एम० उदयपुरवाटी के यहां विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह पार्टी नं० 1 मु०न०


जिला कलेक्टर झुंझुनू

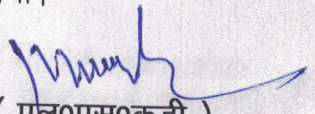
3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 को अन्य दूसरे एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर किया जावे जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके।

वकील अप्राथीगण सं 1 लगायत 3 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र 4/11 में पेश किया था। प्रकरण में मेरीट नहीं देखी जानी है। प्रार्थी रिवीजन में जा सकता है। प्रार्थी द्वारा सुनवाई में देरी के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण का पेश किया गया है। श्रीमान्जी चाहे तो अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को समय सीमा में निर्णय करने हेतु पाबन्द कर सकते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं 4 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नहीं किया गया। एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नहीं है। एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी प्रकरण में निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/ दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते हैं। प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कतई गलत दर्ज किये हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मुझे आपत्ति है। मुकदमा स्थानान्तरण के लिए ठोस कारण नहीं बताये गये हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी में विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह, मु0न0 3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है साथ ही उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि वे अपने यहां लम्बित मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह, मु0न0 3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 का निर्णय 1 माह में आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति न्यायालय एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एस0एस0कुडी)
ज़िला कलक्टर, झुंझुनूं
ज़िला कलक्टर